

(80 per cent) has been accepted by the Ayog as protectable area. A reasonable protection has already been provided to an area of 11.57 million hectares (March, 1981) leaving an area of 20.43 million hectares for providing further protection.

(b) Government of India has provided substantially increased outlays of Rs. 1045 crores during the 6th Plan against Rs. 976 crores provided in all the earlier Plans for expediting the flood control programme. All the States have also been requested to expeditiously implement the recommendations of the Rashtriya Barh Ayog.

### Supply of Rice and Sugar to Kerala

445. SHRI A. NEELALOHITHA-DASAN NADAR: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government of Kerala has requested for the supply of more rice and sugar to Kerala during the coming season; and

(b) if so, the details thereof and action taken thereon?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT (KUMARI KAMLA KUMARI): (a) and (b) The Government of Kerala have requested for enhancement of their monthly quota of rice from the Central Pool from the existing level of 1.10 lakh tonnes to 1.35 lakh tonnes to cope with the increased demand of the cardholders particularly in view of lean months of July-August and the Ramzan and Onam season. The monthly allocation of rice to various States including Kerala is made taking into consideration the overall availability of rice in the Central Pool, relative needs of various States, market availability and other related factors.

No request for supply of more sugar for the coming Onam, has however, been received from the State Government

### मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अधीन 1980-82 के दौरान पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या

446. श्री लक्ष्मण कर्मा : क्या गामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अधीन 1980-82 के दौरान कुल कितने व्यक्तियों ने अपना नाम पंजीकृत कराए और उनमें से कितने व्यक्तियों को 30 जून, 1982 तक रोजगार दिलाया गया ;

(ख) उनको किस प्रकार का तथा वर्ग का रोजगार दिलवाया गया ; और

(ग) सरकार द्वारा खेष व्यक्तियों को रोजगार दिलाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और क्या कार्रवाही की जा रही है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) :

(क) से (ख) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के मार्गदर्शी सिद्धान्तों में ग्रामीण बेरोजगार व्यक्तियों के पंजीकरण के लिए व्यवस्था नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी समर्थ बेरोजगार व्यक्ति चाहे वे पुरुष हों अथवा महिलाएं, अपने क्षेत्रों में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यान्वित किए गए निर्माण कार्यों पर रोजगार पाने के लिए पात्र है। कार्यक्रम के अन्तर्गत सूचित रोजगार अधिकतर गैर-कृशल स्वरूप का होता है, तथापि, कुछ कुशल मजदूरों को भी नियोजित किया जाता है।

कार्यक्रम के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार सृजित रोजगार के श्रमदिनों के बारे में ही सूचना केन्द्रीय स्तर पर प्राप्त की जा रही है। 1980-81 और 1981-82 के दौरान मध्यप्रदेश में कार्यक्रम के अन्तर्गत क्रमशः 661.38 लाख श्रमदिनों और 357.68 लाख श्रमदिनों का रोजगार सृजित होने की सूचना मिली है। 31-3-1982 के पश्चात सृजित रोजगार के आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं।

### Payment of Interest to Allottees

447. SHRI CHANDRADEO PRASAD VERMA: Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to refer to reply given to Unstarred